जनसत्ता

सख्त चेतावनी

भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कम से कम चार ऐसे ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है, जहां से आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराया जाता था। आर्टिलरी गन का इस्तेमाल करते हुए भारतीय सेना ने यह हमला किया। इसमें पाकिस्तान के चार से पांच सैनिकों के भी मारे जाने की खबर है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी सेना लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही थी। उड़ी, बारामूला और तंगधार आदि इलाकों में वह लगातार गोलीबारी कर रही थी। इस तरह उसकी इन हरकतों के चलते पिछले हफ्ते भारतीय सेना के दो जवान और एक नागरिक मारे गए थे। इसकी जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने यह हमला किया। भारतीय सेना लगातार चेतावनी देती रही है कि पाकिस्तानी सेना उसे उकसाने का प्रयास न करे। उसकी हरकतों का सख्त जवाब दिया जाएगा, मगर वह इसे समझने को तैयार नहीं। पिछले एक साल में पाकिस्तानी सेना ने जितनी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, उतना शायद ही कभी हुआ होगा। इसके बावजूद पाकिस्तानी हुकूमत दुनिया भर में यही साबित करने का प्रयास करती रही है कि भारत ही उसे परेशान कर रहा है।

मगर अब पाकिस्तान की इन दलीलों का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कोई असर नहीं होता। जबसे कश्मीर में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाया गया है, पाकिस्तान की खीज लगातार बढ़ती गई है। वह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी में घूम-घूम कर बताता रहा है कि भारत ने कश्मीरी लोगों के साथ अन्याय किया है। मगर हर जगह से उसे मुंह की खानी पड़ी है। कोई भी देश उसके समर्थन में खुल कर सामने नहीं आया है। जो दबी जुबान उसका साथ देते दिख रहे हैं, वे भी उसे कोई बल प्रदान करने वाले नहीं हैं। इससे पाकिस्तान की खीज और बढ़ गई है। इसी का नतीजा है कि वह कश्मीर में अस्थिरता बनाए रख कर भारतीय सुरक्षा-व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास कर रहा है। करीब ढाई महीने तक जब घाटी में कर्फ्यू था और संचार सेवाएं बंद थीं, तब उसकी हरकतें भी बंद थीं। पर अब जनजीवन सामान्य बनाने के इरादे से जब कर्फ्यू हटा लिया गया है, संचार सेवाएं आंशिक रूप से खोल दी गई हैं, उसने चरमपंथी संगठनों को सक्रिय कर दिया है। छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तानी सेना संघर्षविराम का उल्लंघन या बिना उकसावे के गोलीबारी इसलिए करती है कि सीमा पार पनाह पाए आतंकियों की भारतीय सीमा में घुसपैठ करा सके।

पाकिस्तान की समस्या यह है कि वहां कोई एक निजाम नहीं है। वहां की सरकार अपने ढंग से काम करना चाहती है, मगर उस पर सेना और खुफिया एजंसी आइएसआइ का शिकंजा रहता है। सेना अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए भारतीय सीमा पर अस्थिरता बनाए रखना चाहती है। वह युद्ध की धमकी देती तो रहती है, लेकिन उसे यह हकीकत भी अच्छी तरह पता है कि भारतीय सेना के सामने वह टिक नहीं सकती। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में हमले करके जिस तरह भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उससे पहले ही उसे अंदाजा हो गया था। अब तंगधार के उस पार वाले इलाके में आर्टिलरी गन से निशाना बना कर भारतीय सेना ने एक नई रणनीति का परिचय दिया है। पर पाकिस्तान इससे भी कितना सबक सीखेगा, कहना मुश्किल है। संघर्ष विराम और आतंकी घुसपैठ आदि के जरिए वह अपना ही ओछापन जाहिर करता है।

संकल्प और चुनौती

तपेदिक (टीबी) जैसे संक्रामक रोग के खात्मे के लिए भारत ने कमर तो कसी है, लेकिन अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे अभियान में शामिल नहीं हो पाते। जाहिर है, ऐसे टीबी रोगियों के बारे में पता नहीं चलता और उनका समुचित रूप से इलाज नहीं हो पाता। इसका परिणाम टीबी के मरीजों की बढ़ती संख्या के रूप में सामने आता है। भारत में टीबी के मरीजों की तादाद का मोटा अनुमान सिर्फ अस्पतालों में होने वाले पंजीकरण से ही लग पाता है। ऐसे में जो लोग अस्पताल नहीं जाते हैं और इधर-उधर इलाज कराने को मजबूर होते हैं, वे इस गिनती से बाहर रह जाते हैं। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत में पिछले साल टीबी के करीब साढ़े पांच लाख मामले दर्ज होने से रह गए। हालांकि सुकून देने वाली बात यह है कि देश में साल 2018 में टीबी के मरीजों की संख्या में पचास हजार की कमी आई है।

भारत में टीबी आज भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हर साल लाखों लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। इससे भी बड़ी संख्या उन लोगों की है जो हर साल इस बीमारी की जद में आते जा रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आजादी के बहत्तर साल बाद भी आखिरकार भारत टीबी से मुक्ति पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाया। टीबी जैसी बीमारी का सीधा संबंध स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ा है और दुख की बात यह है कि इन दोनों ही मोर्चों पर भारत की स्थिति दयनीय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, जबकि भारत ने इससे दो साल पहले यानी 2023 तक इसके खात्मे का संकल्प किया है। यह एक बड़ी चुनौती इसलिए है कि जितना बड़ा काम है, उसकी तुलना में वक्त और जरूरी संसाधन बहुत कम हैं। दुनिया के सत्ताईस फीसद टीबी मरीज भारत में हैं। समस्या गंभीर इसलिए है कि टीबी के ज्यादातर मामले शुरू में सामने नहीं आ पाते। बीमारी अंदर पनपती रहती है, लेकिन मरीज को कोई ऐसा लक्षण नजर नहीं आता कि उसे जांच कराने की जरूरत महसूस हो। ऐसे में बीमारी बढ़ती चली जाती है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि इस बीमारी के प्रति लोगों में आज भी जागरूकता का अभाव है। शहरी इलाकों में तो फिर लोग अस्पताल चले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इलाज के प्रति सजग भी नहीं है। जाहिर है, टीबी उन्मूलन कोई आसान काम नहीं है।

टीबी कोई ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है जिस पर काबू न पाया जा सके। जब पोलियो, चेचक जैसी महामारियों तक का सफाया हो सकता है, श्रीलंका जैसा देश मलेरिया का नामोनिशान मिटा सकता है तो हम टीबी को जड़ से क्यों नहीं खत्म कर सकते? हमारे यहां बड़ी और गंभीर समस्या गंदगी और प्रदूषण की है जिससे निपटने में ज्यादातर सरकारें नाकाम साबित हुई हैं। शहरों और महानगरों में कूड़ों के पहाड़ इस बीमारी को फैला रहे हैं। देश के ज्यादातर शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण इस बीमारी के प्रमुख कारणों में एक है। सरकार के साथ लोगों को भी साफ-सफाई के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। टीबी से संक्रमित एक मरीज से छह लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। अगर टीबी को मिटाने का संकल्प पूरा करना है तो घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करना होगा, तभी भारत अगले चार साल में टीबी मुक्त हो पाएगा।

कल्पमेधा

अहंकारी व्यक्ति केवल अपने महान कार्यों का वर्णन करता है, और दूसरों के सिर्फ कुकर्मों का।
- स्पिनोजा

फिर सच साबित हुए आइंस्टीन

निरंकार सिंह

ब्लैक होल में हर पल अनगिनत पिंड समा रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में उसके चारों ओर प्रकाश और तरंगों का का एक चक्र बन जाता है, जिससे छत्ते जैसी आकृति बनती है। वैज्ञानिकों ने ऐसी ही छत्ते की तस्वीर खींची है। उन तरंगों के बीच दिख रहा काला हिस्सा ही ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे मानवीय कल्पना को अपनी ओर खींचने वाले स्पेस टाइम फैब्रिक के रहस्य का खुलासा हो सकता है।

ब्रह्मांड में ब्लैक होल यानी अंधेरी सुरंगों की परिकल्पना सबसे पहले सन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। आइंस्टीन के सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल ऐसे खगोलीय पिंड हैं जिनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इनके खिंचाव से बच नहीं सकता। ये पिंड ब्लैक होल इसलिए कहलाते है क्योंकि ये अपने पर पड़ने वाले सारे प्रकाश को सोख लेते हैं और कुछ भी परावर्तित नहीं करते। आइंस्टीन के सिद्धांत से ब्लैक होल के बारे में दुनिया को जानकारी मिली थी। नासा द्वारा जारी की 'सैगिटेरियस ए' नामक ब्लैक होल की तस्वीरों से एक बार उनके सिद्धांत और उनकी परिकल्पना की पुष्टि हुई है। खगोलविदों ने ब्लैक होल के बारे में बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

पहली बार नासा के शोधकर्ताओं ने सूर्य से साठ लाख गुना वजनी ब्लैक होल द्वारा ब्रह्मांडीय उथल-पुथल के तहत एक तारे को टूटते हुए देखा है। इस प्रक्रिया को ज्वारीय विघटन भी कहते हैं। इस विनाशकारी खगोलीय घटना को ग्रहों की खोज के लिए भेजे गए नासा के उपग्रह ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (टीईएसएस), नील गेहरेल्स स्विफ्ट वेधशाला और अन्य उपकरणों की मदद से पहली बार बारीकी से देखा गया। नासा ने बताया कि ब्रह्मांड में ज्वारीय विघटन बहुत ही दुर्लभ घटना है और प्रत्येक दस हजार से एक लाख साल में हमारी आकाशगंगा के बराबर के तारों के पुंज या आकाशगंगा में एक बार यह घटना होती है। अब तक केवल चालीस ऐसी घटना देखी गई हैं।

कैलिफोर्निया स्थित कार्नेजी वेधशाला में इस विषय पर काम कर रहे खगोल भौतिकविद् थॉमस होलोइन के अनुसार टीईएसएस की मदद से यह देखने में मदद मिली कि ब्रह्मांड में घटना वास्तव में कब शुरू हुई जिसे हम पहले कभी नहीं देख सके थे। ज्वारीय विघटन की जल्द ही पहचान धरती पर स्थित ऑल स्काई ऑटोमेटेड सर्वे फॉर सुपरनोवा (एएसएएस-एसएन) से की गई और इस वजह से वे शुरुआती कुछ दिन में बहु-तरंग दैर्ध्य को सक्रिय करके अवलोकन में सफल हुए। इस खगोलीय घटना के समझने के लिए शुरुआती आंकड़े बहुत महत्त्वपूर्ण होंगे। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक यह ब्लैक होल आकाशगंगा के बीच में है। यह वोलंस तारामंडल से करीब सैंतीस करोड़ पचास लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कटे हुए तारे का आकार हमारे सूर्य के बराबर हो सकता है। नासा के मुताबिक इस ब्रह्मांडीय घटना की खोज इस साल 29 जनवरी को विश्व भर में फैले बीस रोबोटिक दूरबीनों वाले एएसएएस-एसएन नेटवर्क की मदद से की गई।

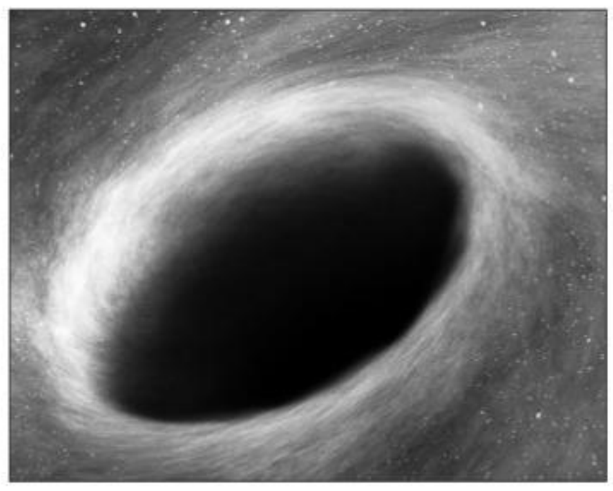

जब होलोइन को नेटवर्क के दक्षिण अफ्रीका में स्थित उपकरण से घटना की जानकारी मिली तब उन्होंने तुरंत चिली के लास कैंपनास स्थित उपकरण से घटना की वास्तविक स्थान का पता लगाने के काम पर लगाया और सटीक नजर रखने के लिए अन्य एजेंसियों की भी मदद ली। टीईएसएस ने पहली बार इस ज्वारीय विघटन को 21 जनवरी को रिकार्ड किया था। इस शोध के सह-लेखक और नेशनल साइंस फाउंडेशन में स्नातक शोधकर्ता पैट्रिक वॉलेली ने कहा कि इस घटना की चमक बहुत स्पष्ट थी, जिसकी वजह से इस घटना की ज्वारीय विघटन के रूप में पहचान करने में मदद मिली। होलोइन की टीम ने बताया कि दूरबीन की मदद से जिस पराबैंगनी रोशनी का पता चला, उसका तापमान महज कुछ दिनों में चालीस हजार डिग्री सेल्सियस से गिर कर बीस हजार डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पहली बार ज्वारीय विघटन के दौरान इतने कम समय में तापमान गिरावट देखी गई है। हालांकि सैद्धांतिक रूप से पहले इसकी जानकारी थी।

अमेरिका स्थित नेशनल साइंस फाउंडेशन ने पिछले महीने वाशिंगटन में इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप (ईएचटी) प्रोजेक्ट के नतीजों का एलान किया था। ईएचटी को ब्लैकहोल की तस्वीर उतारने के लिए ही डिजाइन किया गया था। ब्रसेल्स, टोकियो, सैंटियागो, शंघाई और ताइपे में ब्लैक होल की तस्वीर जारी की गई। अप्रैल 2017 में हवाई, एरिजोना, स्पेन, मैक्सिको, चिली और दक्षिणी गोलार्द्ध में आठ रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किए गए थे। इनकी मदद से ब्रह्मांड के दो अलग-अलग ब्लैक होल के आंकड़े जुटाए गए। एक ब्लैक हमारी गैलेक्सी 'मिल्की वे' के मध्य में स्थित है। 'सैगिटेरियस ए' नामक यह ब्लैक होल 4.4 करोड़ किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका भार सूर्य से चालीस लाख गुना अधिक होने का अनुमान है। दूसरा ब्लैक होल 'एम 87' गैलेक्सी में स्थित है। माना जा रहा है कि यह सैगिटेरियस से भी डेढ़ हजार गुना भारी है। नासा ने पहली बार सैगिटेरियस ए ब्लैक होल की तस्वीरें 11 अप्रैल 2019 को जारी करके इसे बेहद अनोखी घटना बताया।

करीब पचास साल पहले वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के बीच एक चमकीले क्षेत्र का पता लगाया था। साठ के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन आर्कवाल्ड व्हीलर ने उसे 'ब्लैकहोल' का नाम दिया। स्टीफन हाकिंग ने भी ब्लैक होल का व्यापक अध्ययन किया था। उन्होंने ब्लैक होल से निकलने वाले हाकिंग रेडिएशन की परिकल्पना की थी। वैज्ञानिकों के प्रयास से दुनिया ने पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर देखी। असल में किसी भी ब्लैक होल की तस्वीर लेना असंभव है। ब्लैक होल ऐसी संरचना है, जिससे प्रकाश भी वापस नहीं आता। ब्लैक होल की एक सीमा होती है, जिसमें पहुंचते ही कोई भी पिंड घूमते हुए धीरे-धीरे उसके केंद्र में समा जाता है। ब्लैक होल में हर पल अनगिनत पिंड समा रहे होते हैं। इस प्रक्रिया में उसके चारों ओर प्रकाश और तरंगों का का एक चक्र बन जाता है, जिससे छत्ते जैसी आकृति बनती है। वैज्ञानिकों ने ऐसी ही छत्ते की तस्वीर खींची है। उन तरंगों के बीच दिख रहा काला हिस्सा ही ब्लैक होल है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे मानवीय कल्पना को अपनी ओर खींचने वाले स्पेस टाइम फैब्रिक के रहस्य का खुलासा हो सकता है।

इस साल भौतिकी का नोबल ब्रह्मांड की संरचना और इतिहास पर नए सिद्धांत रखने के लिए जेम्स पीबल्स (अमेरिका) और सौरमंडल से बाहर एक और ग्रह खोजने के लिए मेयर व क्वालेज (स्विटजरलैंड) को संयुक्त रूप से दिया गया है। जेम्स पीबल्स ने 1960 के दशक में बिग बैंग, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर जो काम किया था, उसे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान का आधार माना जाता है। इस खोज से हमें पता चला कि ब्रह्मांड के महज पांच प्रतिशत पदार्थ के बारे में ही हम जान पाए हैं। ये वे पदार्थ हैं जिनसे तारे, ग्रह, पेड़-पौधे और हमारा निर्माण हुआ है। बाकी पनचानवे प्रतिशत हिस्सा अज्ञात डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। आइंस्टीन के सिद्धांतों में भी 'डार्क एनर्जी' की जगह थी, हालांकि वे खुद इसके बारे में संशकित थे। वह इसे अपनी एक 'भूल' मानते थे। कुछ वर्ष पहले उनके सिद्धांत की पुष्टि के लिए अमेरिका की 'नेशनल रेडियो स्ट्रोनामिकल आब्जर्वेटरी' ने बृहस्पति ग्रह से पृथ्वी की ओर आती एक प्रकाश किरण की गति और उसके मार्ग की नाप जोख की थी। यह देखा गया कि यह प्रकाश (जो लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक तारे से चला था) जब बृहस्पति के पास गुजर रहा था, तो उसने अपनी दिशा बदल दी और पृथ्वी की ओर मुड़ गया। आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों एक ही है। इसलिए जब कोई किरण किसी ग्रह के पास से गुजरती है तो ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसकी दिशा बदल जाती है। इस प्रयोग से उनकी यह बात सिद्ध हो गई है। 'डार्क एनर्जी' ऐसी अनजानी ऊर्जा है जिसकी वजह से ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है और आकाशीय पिंड एक-दूसरे से दूर जा रहे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का सत्तर फीसद इसी से बना है, हालांकि यह ऊर्जा क्या है, किसी को नहीं पता।

संस्कृति बनाम बच्चे

आलोक कुमार मिश्रा

हाल में मैंने एक खबर पढ़ कर मां को सुनाई तो हैरानी और आश्चर्य से उसका मुंह खुला रह गया। खबर के मुताबिक स्पेन में अदालत ने एक व्यक्ति को दो साल की कैद और दो लाख से अधिक का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। उसका जुर्म यह था कि उसने अपने बेटे का खत खोल कर पढ़ लिया था, जिसे उसकी मौसी ने भेजा था। माना गया कि यह बच्चे की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। मेरी मां का कहना था कि 'भला इसमें क्या बड़ी बात थी! अपने बच्चे के नाम आए खत को मां-बाप क्यों नहीं पढ़ सकते? वह भी जब बच्चा दस वर्ष, छोटी और अपरिपक्व आयु का हो। माता-पिता को अपने बच्चों से जुड़ी बातें जानने और उनके अच्छे-बुरे के बारे में सोचने का हक तो है ही।'

वास्तव में मां की यह टिप्पणी हमारे अपने समाज और संस्कृति की समझ को दर्शा रही थी। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले भी इससे मिलती-जुलती खबर ने हम भारतीयों को काफी उद्वेलित किया था। तब नार्वे में एक भारतीय दंपत्ति से उनकी बेटी को इसलिए अलग कर दिया गया था कि उन पर आरोप था कि वे अपनी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं, साथ ही बिस्तर पर सुलाते हैं जो कि वहां के कानून के अनुसार क्रूरता थी।

बच्चों के अधिकारों से जुड़ी ये खबरें हमें अटपटी इसलिए लगीं कि हम एक बिल्कुल अलग सांस्कृतिक धरातल पर खड़े होकर इन्हें पढ़ और देख-सुन रहे थे। लेकिन नार्वे की घटना यह बताती है कि वहां हमारे तौर-तरीके भी नापसंद किए गए। दरअसल, पश्चिमी देशों में बच्चों के अधिकारों और उनकी निजता को लेकर अतिवादी समझ काम करती दिखती है। लोकतांत्रिक अधिकारों के नाम पर बच्चों को बड़ों द्वारा अच्छे-बुरे की सीख देने, आपस में भावनात्मक रूप से जुड़ कर सीखने-सिखाने के अवसरों को कुंद कर दिया जाता है। जबकि बच्चों को उनकी शारीरिक-मानसिक परिपक्वता प्राप्त करने में बड़ों के सान्निध्य और सहयोग की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में कुछ गलतियां हो सकती हैं, जिन्हें एहसास होने पर सुधारा जा सकता है। पर निजता के कठोर कानून इसकी छूट नहीं देते। ऐसी कठोरता के कारण अभिभावक भी बच्चों को गलत करने पर रोकने-टोकने या उन पर नजर रखने से बचते होंगे। शायद अमेरिका जैसे देशों में कभी-कभी बच्चों द्वारा स्कूलों में बेरोकटोक बंदूक ले जाने, आवेश में आकर गोली चला देने जैसी घटनाएं इसलिए भी दिखती हैं।

दुनिया मेरे आगे

पश्चिमी समाजों की तरह यहां अलगाव, विखंडन और अकेलेपन की समस्या उतनी गंभीर नहीं है और बच्चों या अभिभावकों के बीच इस तरह का कठोर अधिकार विभाजन नहीं दिखता है तो इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं। पश्चिमी समाजों में व्याप्त अति लोकतांत्रिकता के मुकाबले हमारे समाजों में बच्चों को निर्भर-निरीह बना कर रखने और उन पर अभिभावकों का संपूर्ण अधिकार मानने-समझने की चरम स्थिति है। यह बच्चों को एक स्वायत्त और सचेत नागरिक के रूप में विकसित और बड़े होने में बाधा पहुंचाती है। एक ऐसा नागरिक जो समाज में अपनी जिम्मेदारियों और अधिकारों के प्रति सजग होते हुए दूसरों की भिन्नताओं और जीवन दृष्टि के प्रति सम्मान की भावना रखे। लेकिन जब समाजीकरण की प्रक्रिया में ही नियंत्रित रखने और छोटे-बड़े के बीच गैर बराबरी की इतनी सशक्त उपस्थिति हो तो भला बड़े होने पर लोकतांत्रिक चेतना से युक्त व्यक्तित्व कैसे विकसित होगा।

हाल ही में जब हमारे देश की एक राज्य सरकार ने सुरक्षा के नाम पर स्कूली कक्षाओं के अंदर कैमरे लगाने की नीति पर अमल करने की बात कही तो इसका कई आधारों पर समर्थन या विरोध किया गया। पर तर्क देने वालों में अधिकतर प्रशासनिक दृष्टिकोण या शिक्षकों के नजरिए से ही अपनी बात कह रहे थे। इनमें से बहुत कम ने बच्चों की निजता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया। हमारे जैसे सामंती मनोवृत्ति वाले समाजों में जहां बच्चों को वैसे ही अधिकार विहीन, निर्भर और पूरी तरह अपरिपक्व समझा जाता है, उन पर हमेशा नजर बनाए रखने को अच्छे अभिभावक होने की निशानी माना जाता हो, वहां कैमरे नियंत्रण का हथियार ही बनेंगे।

कहने का आशय यही है कि बच्चों और उनके जीवन को लेकर प्रचलित पश्चिमी और भारतीय समाजों की समझ दो विपरीत चरम को दिखाते हैं। संतुलित और सम्यक बचपन के लिए जहां पश्चिमी समाजों से हमें बच्चों को एक नागरिक के रूप में देखे जाने, उनकी निजता और अधिकार को सम्मान दिए जाने की सीख लेनी होगी, वहीं ऐसा करते हुए अभिभावकों की उचित जिम्मेदारी, मार्गदर्शन, देखभाल करने की प्रेमपूर्ण प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति को महत्त्व देना होगा। ऐसा करके हम अकेलेपन, विखंडन और अलगाव की समस्या को दूर कर पाएंगे और साथ ही निर्भर बनाए रखने, नियंत्रण और वर्चस्व की मनोवृत्ति पैदा करने वाले समाजीकरण के चक्र का खात्मा भी कर पाएंगे।

असली मुद्दे गायब

हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इस बार सत्तारूढ़ दल ने जिस तरह से राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया है, उसमें चरम राष्ट्रवाद के प्रदर्शन की झलक मिलती है। इन दोनों राज्यों के गांव, गरीब, किसानों की समस्याओं और बेरोजगारी का कश्मीर और अनुच्छेद 370 से कोई सीधा सरोकार नहीं है। इसके बावजूद इन मुद्दों को उठाना आमजन की समस्याओं से मुंह मोड़ने जैसा है। ऐसे में चुन कर आने वाले जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याओं को लेकर कितने संवेदनशील और उत्तरदायी होंगे, इसमें सन्देह है। चुनाव बाद जनता भी अपनी समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के समक्ष उठाने से इसलिए कतराएगी कि उसकी समस्याएं कभी चुनावी मुद्दा ही नहीं बन पाईं। इससे मूल लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति दुष्कर हो जाएगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुच्छेद 370 हटाया जाना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा गरीब, भुखमरी की शिकार, बेरोजगारी से बेहाल जनता के लिए अप्रासंगिक है।

● *महेंद्र नाथ चौरसिया, सिद्धार्थनगर*

स्वागतयोग्य कदम

साल 2021 से देश के अट्ठाईस सैनिक स्कूलों में अब लड़कियां भी दाखिला ले सकेंगी। उन्हें बीस फीसद तक आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। रक्षा मंत्रालय की इस घोषणा का स्वागत किया जाना चाहिए। अभी उन्नीस और सैनिक स्कूल खोलने पर काम चल रहा है। पहला सैनिक स्कूल आज से अट्ठावन साल पहले सतारा (महाराष्ट्र) में खोला गया था। तबसे से लेकर आज तक इसमें लड़कों को ही प्रवेश दिया जाता है। पर अब इसमें लड़कियां भी शिक्षा हासिल कर सकेंगी। आज बेटियां फौज से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी कामयाबी का परचम लहरा रही हैं तो फिर सैनिक स्कूलों से उन्हें दूर रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। प्रायोगिक परियोजना के तहत मिजोरम में पिछले वर्ष ही लड़कियों को छठी कक्षा में दाखिला दिया जा चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पढ़ाई के मामले में यहां भी बेटियां अव्वल रहेंगी।

● *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

इनका भी रखना है ध्यान

आजकल ऑनलाइन खरीद का चलन बढ़ता जा रहा है। अब तो त्योहारों पर ज्यादातर खरीदारी ऑनलाइन होने लगी है। जूते, कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और सजावट का सामान लोग ऑनलाइन ठिकानों से ही करते हैं। कई ऑनलाइन कंपनियां तो मिट्टी के कलात्मक पात्र, दीये तक बेच रही हैं। इससे देश के छोटे-छोटे कारीगरों की रोजी-रोटी पर बुरा असर पड़ा है। एक छोटा-सा दीपक बनाने में कुम्हार को काफी अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर वह बाजार में बिकने आता है। अच्छा हो, हम सब इन छोटे स्थानीय कलाकारों, कुंभकारों का भी ध्यान रखते हुए मिट्टी के दीये ,मूर्तियां और अन्य सामान इनसे खरीदें, ताकि उनकी कला की भी कद्र हो और वे भी आनंद और उल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मना सकें।

● *संजय डागा, हातोद*

शहरीकरण और पर्यावरण

एक अनुमान के अनुसार देश में वर्ष 2050 तक शहरों की आबादी अस्सी करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। यानी, उस समय की देश की कुल आबादी के पचास प्रतिशत से अधिक हो जाएगी और भारत एक शहरी देश के तौर पर उभर कर सामने आ जाएगा। आज 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, भारत में तिरपन ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी दस लाख से अधिक है। कई अनुसंधानों से यह साबित हो चुका है कि देश में बढ़ते शहरीकरण से आर्थिक विकास की दर तेज होती है और रोजगार के नए अवसर भी गांवों की अपेक्षा शहरों में अधिक बनते हैं। आज भारत में भी देश के सकल घरेलू उत्पाद में शहरी क्षेत्र का योगदान पैंसठ प्रतिशत का है, जिसे बढ़ा कर 75 प्रतिशत तक ले जाना है। बढ़ते शहरीकरण से विभिन्न स्तरों पर सरकारों की जिम्मेदारी भी बढ़ती है, क्योंकि साफ हवा, पीने का साफ पानी, साफ ऊर्जा इन शहरों को उपलब्ध कराना सरकारों की जिम्मेदारी है। शहरों का विकास शुरू में ही यदि उचित तरीके से नहीं किया जाए तो पर्यावरण से संबंधित समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि भारत के कई शहरों में आज देखने को मिल रहा है। सर्दियों के मौसम में शुद्ध हवा का अभाव हो जाता है, शहरों की में स्वच्छ पेयजल का अभाव है। देश में पर्यावरण की स्थिति में सुधार आज वक्त की जरूरत है। लगभग पच्चीस प्रतिशत प्रदूषण वाहनों के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न होता है। हर घर में पौधे लगाने आवश्यक कर देना चाहिए, ताकि वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड गैस कम हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़े। देश में प्रति व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अन्य देशों की तुलना में आज बहुत कम है। जबकि देश में और अधिक शहरीकरण होने के चलते प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अभी तो और आगे बढ़ेगा। अतः उपलब्ध संसाधनों की दक्षता को भी बढ़ाना होगा। कयम हो सके।

● *प्रहलाद सबनानी, ग्वालियर*

पर सड़कें भी तो सुधारें

सड़क परिवहन एवं राज्यमंत्री नितिन गडकरी ने 'वन नेशन वन फास्ट टैग' योजना की शुरुआत की है। यह योजना इस साल एक दिसंबर से संपूर्ण देश में लागू हो जाएगी। इससे लोगों के समय की बचत हो सकेगी। योजना का उद्देश्य टोल के संग्रह को डिजिटल रूप से एकीकृत करना और संपूर्ण भारत में वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना है। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग वाली नई कारों में इस तकनीक के माध्यम से लाभ उठाया जा सकता है। इसके माध्यम से टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम की समस्या से भी मुक्ति मिल सकेगी। इस व्यवस्था के बाद परिवहन मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्गों की बदतर स्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से सड़क हादसों में रोजाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अब समय की मांग है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार किया जाए, ताकि सड़क हादसे में होने वाली मौतों का आंकड़ा कम किया जा सके।

● *अमिता सिंह, अंबेडकरनगर (उप्र)*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com